गरवी गुजरात

TITLE CODE:- UPHIN51504

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 221
दि. 12.12.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

पुतिन के भारत दौरे के बाद पहली बार पीएम मोदी की ट्रंप से फोन पर हुई बात

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करते हुए द्विपक्षीय सहयोग के लगातार मजबूत होने पर संतोष व्यक्त किया।

आधिकारिक बयान के अनुसार, नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के तरीकों पर जोर दिया। उन्होंने महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा और 21वीं सदी के भारत-अमेरिका कॉम्पैक्ट के तहत सहयोग विस्तार पर भी विचार किया।

पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा, " राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बेहद सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और साथ ही क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया। भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता एवं समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में साझा चुनौतियों का समाधान और समान हितों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति बनी। रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने हेतु दोनों संपर्क में रहेंगे।

अमेरिका की संसद में पुतिन-मोदी की फोटो पर हंगामे के बाद ट्रंप ने की बात

बता दें, ट्रंप और पीएम मोदी की ये बातचीत रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत के दौरे की कारपूलिंग तस्वीर पर अमेरिका में छिड़ी बहस के तुरंत बाद हुई है। अमेरिकी कांग्रेस में भारत-अमेरिका संबंधों पर हुई चर्चा के दौरान प्रतिनिधि सिडनी कामलेगर-डव ने इस तस्वीर जिक्र करते हुए ट्रंप प्रशासन की भारत के प्रति अपनाई गई विदेश नीति पर सीधा हमला बोला था।

सांसद डव ने कहा कि "यह फोटो हजार शब्दों के बराबर है। ट्रंप सरकार की भारत नीति को सिर्फ यही कहा जा सकता है कि उन्होंने "अपनी नाक काटकर अपना ही नुकसान किया।" उनके अनुसार, ट्रंप की दबाव वाली कूटनीति ने भारत-अमेरिका संबंधों को कमजोर किया है, और मोदी-पुतिन की कारपूल फोटो इसी कूटनीतिक नुकसान को दिखाती है।"

पुतिन के भारत दौरे के बाद हुई ये फोन पर बात

ट्रंप और पीएम मोदी की ये बातचीत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रधानमंत्री मोदी के साथ उच्च-स्तरीय दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आने के कुछ ही दिनों बाद हुई।

फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद यह पुतिन की भारत की पहली राजकीय यात्रा थी, जिसने वैश्विक ध्यान खींचा।

ट्रंप ने भारत पर फोड़ा था टैरिफ बम

बता दें व्यापक व्यापार तनाव और भारत द्वारा रूसी तेल आयात को लेकर चिंताओं के बीच, ट्रंप ने अगस्त 2025 में अधिकांश भारतीय निर्यातों पर 50% टैरिफ लगाया था।बाजार पहुँच और टैरिफ नीतियों पर विवादों के कारण, 10-11 दिसंबर को भारत आए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल की चर्चाओं में अब तक बहुत कम प्रगति हुई है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंध और तनावपूर्ण हो गए हैं।

बरेली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी का एक्शन मोड, घुसपैठियों पर वार, अधिकारियों को दो टूक, ढिलाई बर्दाश्त नहीं

(जीएनएस)।

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार शाम बरेली पहुंचे तो शहर से लेकर प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। सर्किट हाउस में हुई मंडलीय समीक्षा बैठक में उन्होंने विकास योजनाओं की प्रगति की कड़ी समीक्षा की। सीएम का साफ संदेश था कि ढिलाई बर्दाश्त नहीं, लक्ष्य समय पर और गुणवत्ता से पूरे होने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या किसी कीमत पर नहीं बचने चाहिए। जिले में संचालित संवेदनशील अभियानों पर फीडबैक लिया और पुलिस-प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि अवैध घुसपैठियों पर जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा। बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसी गतिविधियों में शामिल हर व्यक्ति कानून की पकड़ में आना चाहिए।

भारत ने एनआईएसई-टोयोटा फ्यूल सेल वाहन पायलट प्रोजेक्ट के साथ हरित हाइड्रोजन गतिशीलता को बढ़ावा दिया

- श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि समझौता ज्ञापन भारत के स्वच्छ परिवहन के दृष्टिकोण को फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी परीक्षणों के माध्यम से गति देने में महत्वपूर्ण कदम है
- श्री श्रीपाद येसो नाइक ने कहा कि उद्योग-अनुसंधान-सरकारी सहयोग भारत के भविष्य में हाइड्रोजन के इस्तेमाल को गति दे रहा है

(जीएनएस)।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज परिवहन क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग के फील्ड ट्रायल के लिए पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया और इसे भारत की स्वच्छ ऊर्जा प्रगति में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

भारत की ऊर्जा प्रणालियों के लिए भविष्य भविष्य में ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन की स्थिति

केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि वैश्विक स्तर पर हरित हाइड्रोजन भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों की रीढ़ की हड्डी के रूप में उभर रही है। उन्होंने कहा कि यह सहयोग, साथ ही टोयोटा की मिराई हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (एफसीईवी) को वास्तविक परीक्षण के लिए एनआईएसई को सौंपना, भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए नवाचार, उद्योग विशेषज्ञता और वैज्ञानिक सटीकता प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सहयोग "ऊर्जा आत्मनिर्भरता" को मजबूत करते हैं, नवीन और कम उत्सर्जन वाले परिवहन समाधानों को बढ़ावा देते हैं और भारत की पंचामृत जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं, जो सरकार के इस विश्वास की पुष्टि करते हैं कि आने वाले दशकों में हरित हाइड्रोजन देश की ऊर्जा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगी।

टोयोटा की 'मिराई' फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (एफसीईवी) की शुरूआत को "सतत गतिशीलता के लिए एक नया अध्याय" बताते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मिराई नाम का जापानी भाषा में अर्थ "भविष्य" है और यह स्वच्छ, हरित और सतत गतिशीलता इकोसिस्टम के लिए भारत की आकांक्षा का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री ने श्री प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री प्रणब मुखर्जी को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने श्री मुखर्जी को एक महान राजनेता और असाधारण विद्वत्तापूर्ण व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि उन्होंने दशकों के सार्वजनिक जीवन में अटूट समर्पण के साथ देश की सेवा की। श्री मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहाः 'श्री प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वह एक महान राजनेता और असाधारण विद्वत्तापूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे और उन्होंने दशकों के सार्वजनिक जीवन में अटूट समर्पण के साथ भारत की सेवा की। प्रणब बाबू की बुद्धिमत्ता और स्पष्ट विचार ने हर कदम पर हमारे लोकतंत्र को समृद्ध किया।

राष्ट्रपति ने मणिपुर में नागरिक स्वागत समारोह में भाग लिया और इम्फाल में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा- मणिपुर के युवा, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य इसे असीमित संभावनाओं वाला राज्य बनाते हैं
- हमें मिलकर मणिपुर को एक ऐसे राज्य के रूप में मजबूत करना चाहिए जहां प्रत्येक बच्चा सुरक्षित महसूस करे, प्रत्येक महिला सशक्त महसूस करे, प्रत्येक समुदाय अपने को मुख्य धारा में माने और प्रत्येक नागरिक उज्ज्वल भविष्य की ओर आगे बढ़े

(जीएनएस)।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज शाम (11 दिसंबर, 2025) इम्फाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में मणिपुर सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया।

अपने संबोधित में राष्ट्रपति ने कहा कि मणिपुर लचीलेपन, साहस और असाधारण सांस्कृतिक समृद्धि की भूमि है। पीढ़ियों से, यहां के लोगों ने खेल, सशस्त्र बलों, कला और संस्कृति तथा सार्वजनिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अमूल्य योगदान देकर राष्ट्र को समृद्ध किया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि वे मणिपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा के बाद जनता द्वारा झेले गए दर्द से अवगत हैं।

उन्होंने आश्वासन दिया कि मणिपुर की जनता की चिंताओं का ध्यान रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सद्भाव को मजबूत करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिरता एवं समृद्धि की राह पर मणिपुर का समर्थन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार राज्य भर में समान विकास को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगी कि विकास और प्रगति के लाभ राज्य के प्रत्येक कोने तक पहुंचें।

मणिपुर दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के जीवंत सम्बंधों का प्रवेश द्वार है। यहां की युवा पीढ़ी, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता इसे असीमित संभावनाओं वाला राज्य बनाती है। सशक्त महिलाएं मणिपुर की पहचान है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में मणिपुर की बहादुर महिलाओं द्वारा दो बार ऐतिहासिक नुपी लाल या महिला युद्ध लड़े गए। उन्होंने अपनी उचित मांगों को स्वीकार करने के लिए औपनिवेशिक और सामंती शक्तियों को बाध्य करने में सफलता प्राप्त की। वे प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि मणिपुर के लोग प्रतिभाशाली और मेहनती हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों के लोग नए सिरे से सद्भाव बनाए रखेंगे और राज्य को समृद्धि और सुख की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

राष्ट्रपति ने मणिपुर की जनता से सद्भाव और विकास के उपायों का समर्थन जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर मणिपुर को एक ऐसे राज्य के रूप में मजबूत करना चाहिए जहां प्रत्येक बच्चा सुरक्षित महसूस करे, प्रत्येक महिला सशक्त महसूस करे, प्रत्येक समुदाय अपने को मुख्य धारा में माने और प्रत्येक नागरिक उज्ज्वल भविष्य की ओर आगे बढ़े।

इससे पहले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ऐतिहासिक मापाल कांगजेइबुंग में पोलो प्रदर्शनी मैच देखने भी पहुंची।

काशी तमिल संगमम् 4.0 के 10वें दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पाँचवें शैक्षणिक सत्र का सफल आयोजन

- बीएचयू केवल एक शिक्षण स्थल नहीं, बल्कि एक सशक्त सामाजिक संस्थान हैः केंद्रीय राज्यमंत्री श्री जयंत चौधरी
- काशी और तमिलनाडु के बीच आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संबंध सदियों से स्थापित हैंः कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी

(जीएनएस)।

काशी तमिल संगमम् 4.0 के अंतर्गत गुरुवार को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुशल पेशेवरों एवं शिल्पकारों के लिए आयोजित पाँचवाँ शैक्षणिक सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तमिलनाडु से आए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, उद्यमियों और पारंपरिक शिल्पकारों ने इस विशेष सत्र में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जयंत चौधरी, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय तथा राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, ने अपने प्रेरक उद्बोधन में काशी तमिल संगमम् की सराहना करते हुए कहा कि यह आयोजन देश की दो प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को अद्भुत रूप से जोड़ने वाला महत्त्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि भले ही हमारी भाषाएँ और विचार भिन्न हों, किंतु हमारा साझा मूल्य-तंत्र और संविधान हमें एक सूत्र में बाँधता है। भाषा कोई बाधा नहीं, बल्कि वह सेतु है जो तमिलनाडु और काशी को एक परिवार की तरह जोड़ता है।

श्री जयंत चौधरी ने बनारस की आध्यात्मिकता और आकर्षण का उल्लेख करते हुए कहा कि 'कौन बनारस आना नहीं चाहता? यह शहर स्वयं लोगों को अपनी ओर खींच लेता है।' उन्होंने बीएचयू को मात्र एक शिक्षण स्थल न बताते हुए उसे एक सशक्त सामाजिक संस्थान के रूप में वर्णित किया। मार्क ट्वेन के प्रसिद्ध उद्धरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बनारस इतिहास, परंपराओं और किंवदंतियों से भी अधिक प्राचीन है। बदलते वैश्विक परिवेश का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि आज परिवर्तन की गति वर्षों में नहीं, बल्कि क्षणों में मापी जाती है।

ऐसे समय में बीएचयू से यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, नवीन शोध और पेटेंट जैसी उपलब्धियों की अपेक्षा स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी कहा कि आज की युवा पीढ़ी बहुभाषी, संवेदनशील और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली है, और विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय भाषाएँ सीखने के लिए प्रेरित किया।

बीएचयू के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने अपने स्वागत संबोधन में तमिलनाडु से आए अतिथियों का हृदय से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु के बीच आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ज्ञानपरंपरा पर आधारित संबंध सदियों से स्थापित हैं।

गांधीनगर में आयोजित रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एमओयू हुआ

- आणंद जिले के धुवारण में कार्यरत होगा केबल लैंडिंग स्टेशन प्रोजेक्ट

-: महात्मा मंदिर में वन टू वन बैठक आयोजित :-

- प्रोजेक्ट में 1317 करोड़ रुपए का संभावित निवेश होगा तथा 1300 से अधिक प्रत्यक्ष-परोक्ष रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे
- सीएलएस की स्थापना से डेटा सेंटर और आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वृद्धि होगी
- गुजरात हाइपर स्केल और एंटरप्राइज डेटा सेंटर के लिए पसंदीदा स्थान बनेगा
- राज्य सरकार-गिफ्ट सिटी और हेनोक्स आईटी एंड डेटा सेंटर्स के बीच एमओयू

गांधीनगर, 11 दिसंबर : गुजरात में डेटा सेंटर और आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में वृद्धि कर हाइपर स्केल और एंटरप्राइज डेटा सेंटर के लिए गुजरात को डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में इस उद्देश्य से गांधीनगर के महात्मा मंदिर में राज्य सरकार, गिफ्ट सिटी और शारजाह की हेनोक्स आईटी एंड डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एमओयू किया गया।

यह डेटा केबल लैंडिंग स्टेशन प्रोजेक्ट लगभग 1317 करोड़ रुपए के संभावित निवेश के साथ आणंद जिले के धुवारण में आकार लेगा और प्रत्यक्ष-परोक्ष मिलाकर 1300 से अधिक रोजगार अवसरों का सृजन होगा।

गांधीनगर में आयोजित हो रही रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए हेनोक्स आईटी के सीईओ मसूद एम. शरीफ महमूद तथा शारजाह कम्युनिकेशन्स टेक्नोलॉजीस ऑथोरिटी (एससीटीए) के कार्यपालक निदेशक श्री राशिद अल- अली एवं यूएई के भारत स्थित राजदूत डॉ. अब्दुल नासिर जमाल अलशाली ने यह एमओयू करने के बाद मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री से मुलाकात बैठक आयोजित की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि इस सीएलएस प्रोजेक्ट के परिणामस्वरूप आने वाले दिनों में गुजरात में तेज और मजबूत अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी से एआई, मशीन लर्निंग, स्टार्टअप प्लेटफॉर्म और जीसीसी के विकास को गति मिलेगी।

सम्पादकीय

बीएलओज़ को मिली राहत

एसआईंआर की निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईंआर की समय सीमा बढ़ाकर न सिर्प एसआईंआर में शामिल होने वाले नागरिकों को राहत दी है बल्कि इस कार्यंव्रम में कार्यंरत लाखों उन कर्मियों को राहत दी है जो दिन-रात एक करके डेटा संग्राह एवं जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। दरअसल यह कार्यं बेहद संवेदनशील है। जिन लोगों को बीएलओ यानि बूथ लेवल आफिसर बनाया गया है, उन्हें वुछ क्षेत्रों में धमकियां तब मिल रही हैं जब वे सूचनाएं एकत्र कर रहे हैं। यदि जल्दबाजी में सूचनाओं की समीक्षा में गलती हो जाए, तब तो फिर महाभारत होना तय है। असल में चुनाव आयोग ने उन राज्यों में समय-सीमा बढ़ दी है जहां जल्दी चुनाव नहीं हैं किन्तु जिन राज्यों में चुनाव अगले वर्ष है, वहां पर समय सीमा नहीं बढ़ाई है। पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष 2026 में ही चुनाव होना है किन्तु वहां पर एसआईंआर की प्रव्रिया के लिए समय-सीमा बिल्वुल नहीं बढ़ाई गई है। यह सच है कि जिन लोगों के पास अपनी नागरिकता साबित करने के लिए पर्यांप्त सबूत नहीं हैं, उनका न सिर्प मतदाता सूची से नाम कट जाएगा बल्कि उनमें से काफी लोगों की नागरिकता भी खतरे में पड़ जाएगी। यही है कि जो लोग दूसरे देशों से आकर भारत में बसे हैं भले ही वे वर्षो से यहां रह रहे हों किन्तु यदि उन्होंने औपचारिक तरीके से नागरिकता ग्राहण नहीं की है तो उनको डिटेंशन सेंटर में जाने का डर सता रहा होगा। सच तो यह है कि एसआईंआर के पीछे-पीछे एनआरसी भी आने वाली है। मतलब यदि वोटर लिस्ट से नाम कटा तो पहले डिटेंशन सेंटर फिर एनआरसी पूरा होते ही सीएए की औपचारिकता पूरी होनी है। विपक्ष में जो पार्टियां दूसरे देशों के अवैध घुसपैठियों के बल पर चुनाव में वोट बटोरते रहे हैं, उनका यह कहना सच है कि अभी तो काफी वोटर डिटेंशन के डर से भाग रहे हैं। बाकी जो बचेंगे वह एनआरसी के शिकार होंगे। सरकार चाहती भी यही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सरकार कोई भी हो वह किसी देश के अवैध प्रवासियों को स्वीकार वैसे कर सकती है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट रोहिग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर प्रतिवूल टिप्पणी करते हुए उन्हें बाहर निकालने का समर्थन कर चुका है। बहरहाल एसआईंआर में किसी भी तरह से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यह बहुत ही असामान्य कार्यं हो रहा है। यदि जल्दबाजी में किसी भी व्यक्ति को पर्यांप्त अवसर नहीं मिला तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसलिए निर्वाचन आयोग द्वारा हर राज्य में अलग तिथियों तक एसआईंआर की प्रव्रिया समाप्त करने का पैसला बिल्वुल सही है। इस प्रव्रिया के तहत यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो सभी पार्टियों का कर्तव्य है कि सब लोग उक्त पीड़ित को न्याय के लिए संरक्षण दें। किन्तु यह कहना कि समूची एसआईंआर प्रव्रिया ही गलत है, यह उचित नहीं है। लब्बोलुआब यह है कि वर्षो से हमारी प्रवृत्ति रही है कि कौन पूछता है, इसलिए आज इतने घुसपैठिये देश के अलग- अलग राज्यों में फैले हैं। यदि शुरू से ही बीच-बीच में गहन जांच होती रहती तो आज यह नौबत न आती।

प्रधानमंत्री की विजनरी लीडरशिप में एआई राष्ट्रीय प्रगति का मिशन बना है : मुख्यमंत्री

- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने महात्मा मंदिर में रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ कराया
- उप मुख्यमंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की उपस्थिति
- जन सुख-समृद्धि में वृद्धि, पारदर्शिता तथा फ्यूचर रेडी गुजरात के लिए एआई सक्षम संसाधन है : मुख्यमंत्री
- मुख्यमंत्री ने गुजरात यूनिफाइड डिजिटल स्टैक को ऑपरेशनलाइज्ड कर डिजिटल गवर्नेंस को अधिक स्मार्ट, तेज तथा सिटीजन सेंट्रिक बनाने की मंशा व्यक्त की

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- गुजरात ने टेक्नोलॉजी प्रेरित विकास में सदैव अग्रसरता बनाए रखी है
- एग्रीकल्चर, हेल्थ, गवर्नेंस, अर्बन-रूरल ट्रांसफॉर्मेशन पर चिंतन-मंथन विकसित गुजरात@2047 के विजन में नया बल देगा

-: उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी :-

- एआई केवल एक क्षेत्र नहीं; बल्कि नई ऊर्जा है, जो प्रत्येक क्षेत्र को गति के साथ शक्ति दे रही है, गुजरात एआई क्रांति का केन्द्र बनेगा
- निवेशकों तथा एआई स्टार्टअप्स के लिए गुजरात प्लेटफॉर्म बनेगा, उज्ज्वल भविष्य के लिए लॉन्च पैड बनेगा
- 'सुशासन' के लिए वर्तमान समय में एआई सबसे शक्तिशाली टूल्स के रूप में स्थापित : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया
- मुख्यमंत्री के करकमलों से 'गुजरात एआई स्टैक' की लॉन्चिंग तथा 'गुजरात क्लाउड एडॉप्शन गाइडलाइन्स 2025' का अनावरण किया गया
- गुजरात सरकार ने गूगल, भाषिणी, गिफ्ट सिटी तथा हेनोक्स के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए

गांधीनगर, 11 दिसंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्यव्यापी गुजरात यूनिफाइड डिजिटल स्टैक को ऑपरेशनलाइज कर डिजिटल गवर्नेंस को अधिक स्मार्ट, तेज तथा सिटीजन सेंट्रिक बनाने की मंशा व्यक्त की है।

उन्होंने जोड़ा कि इसके परिणामस्वरूप नागरिकों को सभी सेवाएँ एक ही प्लेटफॉर्म से आसानी से मिलने के साथ विभागों के बीच डेटा शेयरिंग तेज बनने से योजनाओं के आउटकम का रीयल टाइम एनालिसिस भी हो सकेगा।

श्री पटेल गुरुवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित हो रही रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ कराते हुए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस अंतर्गत आयोजित एआई एक्सपीरियेंस जोन का उद्घाटन कर विभिन्न स्टार्टअप स्टॉल्स का निरीक्षण किया। इस समारोह में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया उपस्थित रहे।

इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन केन्द्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उपक्रम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में फरवरी-2026 में आयोजित होने वाली एआई इम्पैक्ट समिट के पूर्वार्ध तथा प्री-इवेंट के रूप में किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर गुजरात एआई स्टैक लॉन्च किया। इस एआई स्टैक के लॉन्च होने से सरकारी विभागों में 'प्लग-एंड-प्ले' एआई अपनाने के लिए 6 प्रमुख एआई टूल्स-कृषि एआई, योजना की पात्रता जाँच, प्रोक्योरमेंट चैटबोट, ग्रीवेंस क्लासीफायर, डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रैक्टर तथा चैट मैनेजमेंट टूल से गवर्नेंस

अधिक तेज, सटीक तथा नागरिकोन्मुखी बनेगा।

गुजरात क्लाउड एडॉप्शन गाइडलाइन्स 2025 भी महानुभावों ने लॉन्च की। राज्य के डिजिटल गवर्नेंस को अधिक सुरक्षित, स्केलेबल तथा एआई रेडी बनाने के लिए ये गाइडलाइन्स 2025 में उपयोगी सिद्ध होंगी और टी३एम्पैनल्ड कम्प्यूट का उपयोग आसान बनेगा।

इस कॉन्फ्रेंस में दो महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें गुजरात सरकार – गूगल और भाषिणी के बीच हुए एमओयू के अनुसार बहुभाषीय एआई, गुजराती भाषा मॉडलों और डिजिटल पब्लिक सर्विसेज के लिए रणनीतिक भागीदारी की जाएगी।

इतना ही नहीं; गुजरात सरकार-गिफ्ट सिटी तथा हेनोक्स द्वारा राज्य में केबल लैंडिंग स्टेशन्स (सीएलएस) स्थापित करने के लिए एमओयू किया गया। इससे गुजरात वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी का केन्द्र बनेगा तथा ग्रीन डेटा सेंटर्स को बल प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री की लीडरशिप में एआई केवल टेक्नोलॉजी का संसाधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति का मिशन बन गया है। गुजरात ने सदैव टेक्नोलॉजी प्रेरित विकास में अग्रसरता बनाए रखी है। उन्होंने जोड़ा कि जन सुख-समृद्धि में वृद्धि, पारदर्शिता तथा फ्यूचर रेडी गुजरात के लिए एआई सक्षम संसाधन है।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री की विजनरी लीडरशिप में देश में गत एक दशक में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। छोटे से छोटे व्यक्ति तक टेक्नोलॉजी पहुँची है और इंडिया एआई मिशन शुरू हुआ है। गुजरात ने भी इसके अनुरूप रहकर टास्क फोर्स का गठन किया है।

उन्होंने अपेक्षा दर्शाई कि इस रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में होने वाला सामूहिक मंथन एआई के उपयोग द्वारा टेक्नोलॉजी की मदद से आज के कार्यों से आने वाले कल की क्षमता के दृष्टिकोण को बदलने में उपयोगी बनेगा।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने गुजरात को एआई क्रांति का निर्माण करने वाला राज्य बताया और निवेशकों तथा एआई स्टार्टअप्स का गुजरात में स्वागत किया।

श्री संघवी ने कहा कि गुजरात सदैव 'अतिथि' तथा 'इनोवेशन'-इन दो शक्तिशाली परिबलों का स्वागत करता आया है। हमारा लक्ष्य 'मन वर्सेज मशीन नहीं, बल्कि 'मन विद मशीन है, जहाँ मानव कल्पना ने एक ऐसे पार्टनर का निर्माण किया है, जो कल्पना भी कर सकता है। एआई अब केवल एक क्षेत्र नहीं, बल्कि नई ऊर्जा है, जो प्रत्येक क्षेत्र को गति के साथ शक्ति दे रही है।

उन्होंने गुजरात में विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे एआई आधारित उपयोगों पर प्रकाश डालते हुए जोड़ा कि गिफ्ट सिटी में माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से स्थापित एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) भारत के आगामी टेक इकोसिस्टम को आकार दे रहा है। यह हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग तथा शिक्षा जैसे क्षेत्रों में गति दे रहा है। गुजरात में कृषि क्षेत्र में फसल एआई प्लेटफॉर्म द्वारा किसानों को पानी की बचत करने तथा कीटाणुनाशकों का उपयोग कम करने में मदद मिल रही है। कृषि प्रगति प्लेटफॉर्म पर एक लाख से अधिक किसानों को फसल के स्वास्थ्य, भूमि की स्थिति तथा जल की उपलब्धता के बारे में एआई आधारित सलाह मिल रही है, जो उनकी आय बढ़ाने में सहायक है। इसके अतिरिक्त; सिम्बा-एसआईएमबीए प्रोजेक्ट द्वारा वन्यजीवों की रक्षा की जा रही है। सार्वजनिक परिवहन सेवा जीएसआरटीसी में भी कार्यक्षमता सुधारने के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है।

श्री संघवी ने गुजरात पुलिस द्वारा नागरिक सुरक्षा के लिए एआई टेक्नोलॉजी के किए गए उपयोग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अहमदाबाद में आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथजी की रथयात्रा में पुलिस ने एआई सवेलांस के जरिए 5,481 गुमशुदा बच्चों को खोजकर उनका परिवार से पुनर्मिलन कराया। इतना ही नहीं, सुदूरवर्ती तथा ट्राइबल क्षेत्र माने जाने वाले दाहोद जिले में पुलिस ने अवैध गांजे की खेती के विरुद्ध राज्य का पहला एआई आधारित ऑपरेशन चलाया। मशीन-लर्निंग मॉडलों ने गांजे के पौधों को पहचाना और ड्रोन सवेलांस से 1.19 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का गांजा पकड़ा। इसके अलावा, अंबाजी मेले में एआई सवेलांस ने संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक कर गुमशुदा व्यक्तियों को खोजा तथा भीड़ प्रबंधन को मजबूत बनाया।

श्री हर्ष संघवी ने सभी निवेशकों और एआई स्टार्टअप्स को गुजरात में निवेश करने, निर्माण करने तथा अपने सपने साकार करने के लिए आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा, 'गुजरात आपका प्लेटफॉर्म बनेगा। गुजरात आपके भविष्य का लॉन्च पैड बनेगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि सुशासन के लिए वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआई सबसे शक्तिशाली टूल्स के रूप में स्थापित हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात एआई क्षेत्र में अग्रसर रहा है। एआई के माध्यम से टेक्नोलॉजी, डेटा स्टोरेज, दैनिक कार्य में तेजी और पारदर्शिता आई है, जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों को घर बैठे सुविधा देने सहित विभिन्न सेवाओं में बड़ा परिवर्तन आया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत एआई तकनीक में नई ऊँचाइयाँ छू रहा है। पुरानी और नई पीढ़ी रेडियो, टीवी, कंप्यूटर और अब एआई तकनीक क्षेत्र में आने वाले बदलाव की साक्षी बनी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गुजरात में आयोजित यह 'रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस' भविष्य में एआई क्षेत्र में नई क्रांति लाएगी।

टी३ के अपर सचिव और एनआईसी के महानिदेशक श्री अभिषेक सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिशानिर्देशन में भारत में आगामी फरवरी 2026 में 'एआई इम्पैक्ट समिट' आयोजित होगी। विश्व में पहली बार किसी विकासशील देश में वैश्विक स्तर की एआई समिट आयोजित होगी। इस समिट को अधिक सार्थक बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक राज्य में भी रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का आह्वान किया था, जिसके परिणामस्वरूप आज यह कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई टेक्नोलॉजी के क्रियान्वयन में गुजरात हमेशा देश में लीड लेकर अग्रसर रहा है। अब एआई के क्षेत्र में भी गुजरात देश के लिए रोल मॉडल बनेगा।

इस रीजनल कॉन्फ्रेंस में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव श्रीमती पी. भारती ने स्वागत संबोधन में एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत आयोजित होने वाले विभिन्न थीमैटिक सत्रों की विस्तृत भूमिका देते हुए कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान एआई फॉर एग्रीकल्चर, हेल्थकेयर, गवर्नेंस, अर्बन- रूरल ट्रांसफॉर्मेशन और फिन-टेक जैसे पाँच विषयों पर राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जाएगी तथा वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली 'एआई इम्पैक्ट समिट' के लिए मूल्यवान सिफारिशें भी की जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में गुजरात इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री अरविंद विजयन ने आभार व्यक्त किया।

रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि, गिफ्ट सिटी के प्रबंध निदेशक श्री संजय कौल, शारजाह कम्युनिकेशन्स टेक्नोलॉजीस ऑथोरिटी के कार्यपालक निदेशक श्री राशिद अली अल-अली, गुजकोस्ट के सलाहकार श्री नरोत्तम साहू, भारत और गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, वैश्विक टेक कंपनियाँ, आईआईटी, उद्योग जगत के विशेषज्ञ तथा 100 से अधिक स्टार्टअप्स से जुड़े इनोवेटर्स उपस्थित रहे ।

भारतीय रेल ने 812 मेगावाट सौर ऊर्जा और 93 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करके नवीकरणीय ऊर्जा को गति दी

भारतीय रेल ने 812 मेगावाट सौर ऊर्जा और 93 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करके प्रचालन क्षमता बढ़ाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को गति दी; 1,600 मेगावाट की चौबीसों घंटे चलने वाली हाइब्रिड बिजली परियोजना के लिए भी समझौता किया

भारतीय रेल ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया, सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से बिजली आवश्यकताओं की पूर्ति जारी

ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.2 प्रतिशत हिस्सा पहले ही विद्युतीकृत; 2014 से अब तक रूट विद्युतीकरण दोगुने से भी अधिक हुआ जो छह दशकों में 21,801 किमी से बढ़कर 2014-25 के बीच 46,900 किमी तक पहुंचा

(जीएनएस)।

भारतीय रेल सुरक्षा, समयबद्धता, विश्वसनीयता और यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकीयों के अंगीकरण के साथ अपनी अवसंरचना और रेलगाड़ियों का निरंतर उन्नयन कर रहा है। ये उन्नयन प्रणाली के आधुनिकीकरण और यात्रियों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किए जा रहे समन्वित प्रयासों को दशार्ते हैं।

आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने और रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण के साथ, कोयला आधारित इंजनों और डीजल इंजनों के उपयोग में कमी आई है।

भारतीय रेल में रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य मिशन मोड में शुरू किया गया है। अब तक, ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग 99.2 प्रतिशत विद्युतीकृत हो चुका है। शेष नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य जारी है। 2014-25 के दौरान और 2014 से पहले किए गए विद्युतीकरण का विवरण इस प्रकार है:

अवधि-मार्ग किमी-2014 से पहले (लगभग 60 वर्ष) 21,801, 2014-25, 46,900

भारतीय रेल अत्याधुनिक तीन-चरण आईजीबीटी प्रौद्योगिकी आधारित लोकोमोटिव का विनिर्माण और कमीशनिंग कर रही है। इन लोकोमोटिव में रिजेनेरेटिव विशेषताएं हैं जिसके कारण ये ब्रेकिंग के दौरान खपत होने वाली ऊर्जा के एक हिस्से को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम हैं और इस प्रकार अधिक ऊर्जा कुशल हैं।

कोयले से चलने वाले इन भाप इंजनों का उपयोग यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पर्वतीय रेलमार्गों, मौसमी भाप से चलने वाली ट्रेनों और आईसीआरटीसी के सहयोग से किराए पर ली गई रेलगाड़ियों में किया जा रहा है। इनका उपयोग विरासत महत्व वाले रेलवे मार्गों पर किया जाता है।

भारतीय रेल ने कार्यनीतिक विद्युत खरीद योजना के आधार पर सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संयोजन से कर्षण (ट्रैक्शन) प्रयोजन के लिए अपनी विद्युत शक्ति की आवश्यकता प्रगतिशील तरीके से पूरी करने की योजना बनाई है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।

नवंबर 2025 तक, लगभग 812 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र और लगभग 93 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्र कमीशन हो चुके हैं, जो भारतीय ऊर्जा क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से चौबीसों घंटे (आरटीसी) मोड के तहत प्राप्त 100 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का प्रवाह भी ट्रैक्शन प्रयोजन के लिए आरंभ हो चुका है।

इसके अतिरिक्त, ट्रैक्शन पावर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आरटीसी मोड के तहत 1,500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को भी शामिल किया गया है।

मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों से टिकट आरक्षण प्रणाली की गई और दुरूस्त

भारतीय रेल ने मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों से टिकट आरक्षण प्रणाली को और भी दुरूस्त किया

जनवरी 2025 से अब तक 3.02 करोड़ संदिग्ध यूजर आईडी निष्क्रिय; प्रामाणिक टिकट बुकिंग के लिए एंटी-बॉट उपाय लागू

ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए 322 रेलगाड़ियों और आरक्षण काउंटरों पर 211 रेलगाड़ियों में आधार-आधारित ओटीपी सत्यापन लागू

96 लोकप्रिय रेलगाड़ियों में से 95 प्रतिशत रेलगाड़ियों में तत्काल टिकट की उपलब्धता का समय बढ़ाया गया

(जीएनएस)।

भारतीय रेल की आरक्षण टिकट बुकिंग प्रणाली एक मजबूत और अत्यधिक सुरक्षित आईटी प्लेटफॉर्म है जो उद्योग-मानक और अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा नियंत्रणों से सुसज्जित है। भारतीय रेल ने आरक्षण प्रणाली के प्रदर्शन और नियमित/तत्काल टिकटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. उपयोगकर्ता खातों का कड़ा पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन किया गया है। जनवरी 2025 से अब तक लगभग 3.02 करोड़ संदिग्ध उपयोगकर्ता आईडी निष्क्रिय कर दी गई हैं।

2. अकामाई जैसे एंटी-बॉट समाधानों को फर्जी उपयोगकताओं को हटाने और वैध यात्रियों के लिए सुचारू बुकिंग सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।

3. तत्काल बुकिंग में दुरुपयोग को रोकने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग हेतु आधार आधारित वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) सत्यापन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। 4 दिसंबर 2025 तक यह सुविधा 322 रेलगाड़ियों में पहले से ही मिल रही है। उपरोक्त उपायों के परिणामस्वरूप, उपर्युक्त 322 रेलगाड़ियों में से लगभग 65 प्रतिशत रेलगाड़ियों में तत्काल टिकट की उपलब्धता का समय बढ़ गया है।

4. आरक्षण काउंटरों पर तत्काल बुकिंग के लिए आधार-आधारित ओटीपी को भी चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया है और 04.12.2025 तक इसे 211 रेलगाड़ियों में लागू किया गया है।

5. इन और अन्य उपायों के परिणामस्वरूप, 96 लोकप्रिय रेलगाड़ियों में से लगभग 95 प्रतिशत रेलगाड़ियों में तत्काल टिकट की उपलब्धता का समय बढ़ गया है।

6. संदिग्ध रूप से बुक किए गए पीएनआर के संबंध में राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायतें दर्ज की गई हैं।

7. साइबर खतरों से सिस्टम की सुरक्षा के लिए नेटवर्क फायरवॉल, घुसपैठ रोकथाम प्रणाली, एप्लिकेशन डिलीवरी कंट्रोलर और वेब एप्लिकेशन फायरवॉल जैसी कई सुरक्षात्मक परतों का उपयोग किया गया है। यह सिस्टम एक समर्पित, एक्सेस-नियंत्रित डेटा सेंटर में लगाया गया है, जो सीसीटीवी निगरानी और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित है। डेटा सेंटर आईएसओ 27001 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) मानकों के अंतर्गत प्रमाणित है।

साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड व्यापक साइबर खतरा खुफि या सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें टेक-डाउन सेवाएं, खतरा निगरानी, डीप और डार्क वेब निगरानी और डिजिटल जोखिम सुरक्षा शामिल हैं। ये सेवाएं उभरते साइबर खतरों के बारे में सक्रिय और कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करती हैं और बेहतर घटना प्रतिक्रिया को संभव बनाती हैं।

8. आरक्षण प्रणाली की नियमित सुरक्षा जांच सीईआरटी-इन सूचीबद्ध सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा एजेंसियां करती हैं। इसके अतिरिक्त, साइबर हमलों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए सीईआरटी-इन और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) टिकट प्रणाली से संबंधित इंटरनेट यातायात की निरंतर निगरानी करती है।

इसके अतिरिक्त, रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे, मंडल कार्यालय आदि विभिन्न स्तरों पर जन प्रतिनिधियों/संगठनों/रेल उपयोगकताओं आदि से औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के अनुरोध/सुझाव/प्रतिनिधित्व प्राप्त होते रहते हैं। चूंकि ऐसे अनुरोध/सुझाव/प्रतिनिधित्व की प्राप्ति एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए इनका कोई केंद्रीकृत संकलन नहीं रखा जाता है। हालांकि, इनकी समय-समय पर जांच की जाती है और व्यवहार्य एवं उचित पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है, जो एक निरंतर प्रक्रिया है।

यह जानकारी रेल. सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

'हाइड्रोजन से चलने वाला यात्री पोत गंगा में रवाना हुआ, जो मोदी सरकार के नेतृत्व में नेट-जीरो जलमार्गों की दिशा में एक बड़ा कदम है' - सरबानंदा सोनोवाल

- भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का वाराणसी में वाणिज्यिक सेवा शुरू; सरबानंदा सोनोवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
- देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामरान जहाज शून्य उत्सर्जन वाला, स्वदेशी 24 मीटर लंबा स्वच्छ प्रणोदन वाला पोत है, जिसमें 50 सीटों की क्षमता है

(जीएनएस)।

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सरबानंदा सोनोवाल ने वाराणसी के नमो घाट पर देश के पहले पूरी तरह से स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री पोत के वाणिज्यिक संचालन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह भारत ने अपने हरित समुद्री प्रयासों में एक बड़ा कदम उठाया है।

यह पोत भारत में समुद्री परिवेश में हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणोदन का प्रदर्शन करने वाला पहला पोत है। इसमें पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया गया है। यह एक निम्न तापमान प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन ईंधन सेल प्रणाली पर संचालित होता है जो संग्रहित हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करता है और उप-उत्पाद के रूप में केवल पानी उत्सर्जित करता है।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सरबानंदा सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत स्वच्छ, सतत और आत्मनिर्भर परिवहन प्रणालियों की ओर एक परिवर्तनकारी बदलाव देख रहा है। हमारे पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का शुभारंभ प्रधानमंत्री की 'मेक इन इंडिया' की प्रतिबद्धता और सभी क्षेत्रों में हरित गतिशीलता की ओर प्रगति का एक शानदार उदाहरण है। यह उपलब्धि हमारी पवित्र गंगा के पुनरुद्धार और संरक्षण के व्यापक मिशन को भी मजबूत करती है। जैसे-जैसे हम अपने जलमार्गों पर स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ा रहे हैं, हम न केवल नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास पारिस्थितिक जिम्मेदारी के साथ-साथ चले। आज की उपलब्धि हमारे राष्ट्र के लिए एक हरित और अधिक समृद्ध समुद्री भविष्य के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री के अटूट संकल्प को दशार्ती है ।

भारतीय अंतदेर्शीय जलमार्ग प्राधिकरण के स्वामित्व वाला यह पोत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था। परीक्षण संचालन पूरा होने के बाद पोत सेवा में सम्मलित हुआ। यह कदम वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है और भारत के अंतदेर्शीय जलमार्गों में स्वच्छ, सतत ईंधन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के प्रयासों का समर्थन करता है।

हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत की वाणिज्यिक सेवा की शुरूआत भारत के स्वच्छ और अधिक टिकाऊ समुद्री इकोसिस्टम के निर्माण के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री सोनोवाल के नेतृत्व में, भारतीय अंतदेर्शीय जलमार्ग प्राधिकरण समुद्री भारत विजन 2030 और समुद्री अमृत काल विजन 2047 के अंतर्गत उन्नत हरित प्रौद्योगिकियों और वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने को बढ़ावा दे रहा है।

सरबानंदा सोनोवाल ने कहा कि इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत की सफल तैनाती स्वच्छ और सतत जलमार्गों की ओर भारत के परिवर्तन को गति देने के लिए हमारे मंत्रालय की गहरी प्रतिबद्धता को दशार्ती है । मैं इस अग्रणी पोत की डिलीवरी के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और कठोर परीक्षणों के बाद इसे वाणिज्यिक सेवा में शामिल करने के

लिए भारतीय अंतदेर्शीय जलमार्ग प्राधिकरण को बधाई देता हूं। यह उपलब्धि वर्ष 2070 तक भारत के नेट-जीरो लक्ष्यों को पूरा करने और अंतदेर्शीय जल परिवहन क्षेत्र में अत्याधुनिक हरित प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के हमारे संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के परिवर्तनकारी समुद्री भारत विजन (एमआईवी) 2030 और समुद्री अमृत काल विजन (एमएकेवी) 2047 के दीर्घकालिक रोडमैप के मार्गदर्शन में , हम देश के लिए एक आधुनिक, ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार समुद्री इकोसिस्टम को निरंतर आकार दे रहे हैं। शहरी परिवहन के लिए डिजाइन की गई 24 मीटर लंबी कैटामरान नाव, वातानुकूलित केबिन में 50 यात्रियों को ले जा सकती है और 6.5 समुद्री मील की गति से चलती है। इसकी हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली में हाइड्रोजन ईंधन सेल, बैटरी और सौर ऊर्जा का संयोजन है, जिससे एक बार हाइड्रोजन भरने पर यह आठ घंटे तक चल सकती है। यह पोत भारतीय जहाजरानी रजिस्टर द्वारा प्रमाणित है।

पायलट पोत एफसीवी पायलट-01 को चालू करने के लिए, भारतीय अंतदेर्शीय जलमार्ग प्राधिकरण, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड ने तकनीकी सहायता, संचालन और निगरानी को रेखांकित करते हुए एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। इस समझौते में वित्तीय शर्तें, सुरक्षा प्रक्रियाएं, निगरानी तंत्र और पायलट चरण के दौरान आवधिक निरीक्षण के प्रावधान शामिल हैं।

वाराणसी में शुरू की गई हाइड्रोजन ईंधन सेल वाली नौका शहरी जल परिवहन को कई महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाती है, जिनमें यात्रियों और तीर्थयात्रियों के लिए शोर-मुक्त यात्रा, केवल जल उत्सर्जन के साथ शून्य धुआं और शून्य प्रदूषण, और जलमार्गों के माध्यम से तेज आवागमन से सड़क पर भीड़भाड़ में कमी शामिल है। इससे स्थानीय पर्यटन और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, साथ ही वाराणसी हाइड्रोजन-संचालित यात्री परिवहन को अपनाने वाले विश्व के पहले शहरों में से एक बन जाएगा । तकनीकी रूप से, पूरी तरह से वातानुकूलित 50 सीटों वाली यह नौका संग्रहित हाइड्रोजन पर आठ घंटे तक चल सकती है, 7 से 9 समुद्री मील की गति से चलती है, और पूरी तरह से स्वदेशी, पर्यावरण के अनुकूल तकनीक द्वारा संचालित है जो सुरक्षित और कुशल संचालन सुनिश्चित करती है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

पश्चिम रेलवे चलाएगी उर्स उत्सव के दौरान बांद्रा टर्मिनस और अजमेर के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा अजमेर उर्स उत्सव के दौरान यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान रखते हुए बांद्रा टर्मिनसझअजमेर स्टेशन के बीच विशेष किराए पर स्पेशल ट्रेन चलायी जाएगी। इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार है:

ट्रेन संख्या 09063/09064 बांद्रा टर्मिनस-अजमेर सुपरफास्ट स्पेशल [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 09063 बांद्रा टर्मिनस-अजमेर स्पेशल बुधवार, 24 दिसंबर, 2025 को 12:15 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 06:15 बजे अजमेर पहुंचेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09064 अजमेर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल गुरुवार, 25 दिसंबर, 2025 को 11:40 बजे अजमेर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 04:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, नडियाद, साबरमती, महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, पिण्डवाड़ा, फालना, रानी, मारवाड़, सोजत रोड और ब्यावर स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में अउ - 2 टियर, अउ - 3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09063 के लिए बुकिंग 12 दिसंबर 2025 से सभी ढफर काउंटरों और क्मठळउ वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन-भावनगर मंडल द्वारा निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं का भव्य सम्मान समारोह आयोजित

(जीएनएस)।

पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन-भावनगर मंडल द्वारा रेलवे कर्मचारियों के आश्रित बच्चों में रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित निबंध लेखन तथा चित्रकला एवं पेंटिंग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित करने हेतु दिनांक 11 दिसंबर, 2025 (गुरूवार) को एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विजेताओं को प्रमाण-पत्र व नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम रेलवे ऑफिसर्स क्लब, भावनगर परा में संपन्न हुआ।

महिला कल्याण संगठन द्वारा निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन 14 सितम्बर 2025 को तथा चित्रकला एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन 21 सितम्बर 2025 को किया गया था। इन दोनों प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित विजेता प्रतिभागियों को संगठन की अध्यक्षा श्रीमती शालिनी वर्मा द्वारा सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान भावनगर मंडल सांस्कृतिक संघ के सदस्यों तथा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, भावनगर रेलवे मंडल के सदस्यों को भी उनके योगदान एवं सक्रिय सहभागिता हेतु संगठन की अध्यक्षा द्वारा सम्मानित किया गया।

सम्मान समारोह में विजेता प्रतिभागी अपने अभिभावकों के साथ उपस्थित रहे। इस अवसर पर महिला कल्याण संगठन-भावनगर मंडल की उपाध्यक्ष श्रीमती मोनिका शर्मा, सेक्रेटरी श्रीमती माया त्रिपाठी, ट्रेजरर श्रीमती वंदना पाटीदार, कल्चरर इंचार्ज श्रीमती रश्मि मलिक, कैटरिंग इंचार्ज श्रीमती शिखा राणा तथा अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहीं।

महिला कल्याण संगठन-भावनगर मंडल द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम न केवल बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करता है, बल्कि उन्हें प्रेरित कर उनके बहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना के तहत 13 दिसंबर तक करें आवेदन : डीसी

सुशासन दिवस पर राज्य व जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों व टीम को किया जाएगा पुरस्कृत

(जीएनएस)।

रेवाड़ी। हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना के अंतर्गत आगामी 25 दिसंबर 2025 को साल 2024-2025 में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को 'गुड गवर्नेंस अवॉर्ड' दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना के अंतर्गत उन अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरस्कृत कर शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है, जिनके अभिनव, अभ्यास और असाधारण प्रयास पूरे राज्य में बेहतर शासन में योगदान करते हैं।

डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सुशासन पुरस्कार के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगम, सोसाइटी, विश्वविद्यालय, हरियाणा सरकार के अधीन उपक्रम के सभी पात्र कर्मचारी (रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट वाले) अपने-अपने ऑफिस-हेड या विभागाध्यक्ष या संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के जरिए ऑनलाइन पोर्टले पर 13 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें प्रोजेक्ट/स्कीम/प्रोग्राम का चयन करने उपरांत नॉमिनेट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, विभागाध्यक्ष और आईएएस ऑफिसर को इनमें शामिल नहीं किया गया है।

डीसी ने बताया कि सभी इच्छुक अधिकारियों/अधिकारियों या कर्मचारियों की टीम, जिन्होंने बहुत अच्छा और इनोवेटिव काम किया है, वे अपने आवेदन विभागाध्यक्ष/विभाग के कार्यालय/संगठन को भेज सकते हैं, जिनकी उनके द्वारा जांच की जाएगी और अपनी सिफारिशों के साथ आगे भेजी जाएगी। स्टेट अवॉर्ड सभी कर्मचारियों के लिए पोर्टल पर अपलोड करने के लिए खुला है, जो स्टेट लेवल पर दिए जाएंगे और हर जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट-लेवल अवॉर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिए जाएंगे। कोई भी डिपार्टमेंट अपने-अपने डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा स्कीम के लिए कर्मचारी का नाम प्रस्तावित कर सकता है। उन्होंने बताया कि सभी विजेताओं को एक ट्रॉफी, मुख्य सचिव के हस्ताक्षर किया हुआ अवॉर्ड सर्टिफिकेट और नकद इनाम दिया जाएगा। इससे संबंधित विस्तार से जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता

समाधान शिविर में मौके पर ही बनाई पेंशन, सरकार का किया धन्यवाद

(जीएनएस)।

रेवाड़ी। हरियाणा सरकार की पहल पर जिला प्रशासन की ओर से जिला मुख्यालय सहित उपमंडल स्तर पर लगाए जा रहे समाधान शिविर आमजन की शिकायतों का समाधान करवाने में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। समाधान शिविर में नागरिकों को एक ही स्थान पर अपनी शिकायतों व समस्याओं का समाधान करवाने का अवसर मिल रहा है। डीसी अभिषेक मीणा ने गुरुवार को जिला सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर की अध्यक्षता करते हुए जन शिकायतों का मौके पर ही समाधान करवाकर आमजन को राहत पहुंचाई।

डीसी अभिषेक मीणा ने समाधान शिविर में मौके पर ही कंवाली निवासी नरेश कुमार की अविवाहित पेंशन बनवाई, जिस पर नरेश कुमार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हुए कहा कि समाधान शिविर में लोगों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जाता है, जिससे लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। इसके अलावा गांव भाड़ावास में खेत के रास्ते से मिट्टी उठाने पर डीसी ने खनन अधिकारी को जांच करते हुए जुमार्ना लगाने के निर्देश दिए। गांव जैतड़ावास में रास्ते पर हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत पर डीसी ने डीडीपीओ को अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए। गांव डहीना में

पंचायती रास्ते की पैमाइश करवाने के लिए संबंधित नायब तहसीलदार को निर्देश दिए। सेक्टर-3 सीवरेज चैंबर व नाले की साफ-सफाई करवाने के लिए नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए। कालाका रोड पर वार्ड नंबर 6 में गली कौ मिट्टी से लेवलिंग करने के लिए नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए। समाधान शिविर में नागरिकों द्वारा मुख्य रूप से फैमिली आईडी में सदस्य जोडने. से संबंधित, राशन कार्ड, पुलिस विभाग, बिजली विभाग से संबंधित समस्याएं प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही समाधान करवा दिया गया। वहीं शेष बची शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

डीसी ने कहा कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आमजन की शिकायतों को नजरअंदाज करना किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारी आमजन की शिकायतों के निवारण की दिशा में तत्परता से कार्रवाई कर उन्हें राहत पहुंचाए। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन हर सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से 12 बजे तक लघु सचिवालय में जनता की समस्याएं सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन नागरिकों की सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं और जनहित में यह पहल निरंतर जारी रहेगी।

इस अवसर पर एडीसी राहुल मोदी, एसडीएम रेवाड़ी सुरेश कुमार, भाजपा नेता हुकमचंद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

श्री पीयूष गोयल ने पारदर्शिता बढ़ाने, उद्योग-सरकार सहयोग और दक्षता में सुधार का आह्वान किया

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एसईईपीजेड) में एनईएसटी-02 (न्यू एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज टावर-चरण 2) का उद्घाटन किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई के सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एसईईपीजेड) में एनईएसटी-02 (न्यू एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज टावर-चरण 2) का उद्घाटन किया और उद्योगों से भारत की भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौशल विकास पहलों को उल्लेखनीय रूप से मजबूत करने का आग्रह किया।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हासिल की गई विकास की गति को एसईईपीजेड में भी बरकरार रखा जाना चाहिए और कहा कि क्षेत्र को अपने कार्यप्रणाली और प्रदर्शन को राष्ट्र की व्यापक आर्थिक गति के अनुरूप बनाना होगा।

श्री गोयल ने एसईईपीजेड इकाइयों को प्रशिक्षण प्रयासों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें विशेष रूप से सक्षम युवाओं के लिए पहल भी शामिल है और कहा कि कौशल विकास भारत के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने उद्योग जगत से कार्यबल विकास में सहयोग देने और व्यापक राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंडा में योगदान देने में अधिक जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया।

मंत्री ने कहा कि पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के शासन दृष्टिकोण के केंद्र में बनी हुई हैं। उन्होंने इकाई धारकों और उद्योग प्रतिनिधियों से प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसईईपीजेड स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालित हो, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे वातावरण को बनाए रखना एक साझा जिम्मेदारी है।

श्री गोयल ने कहा कि स्थान के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने और दुरुपयोग को रोकने के लिए नीलामी आधारित आवंटन और पारदर्शी प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। उन्होंने हितधारकों को सामूहिक रूप से अप्रयुक्त भूखंडों की समीक्षा करने और निर्यात क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाने हेतु प्रबंध समिति के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अनुमोदन, सीमा शुल्क संचालन, रखरखाव अनुबंध और अन्य प्रशासनिक मामलों से संबंधित प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया।

मंत्री ने एसईईपीजेड में चल रहे और नियोजित बुनियादी ढांचा उन्नयन की समीक्षा की, जिसमें आंतरिक सड़कों, हरियाली और पूरे क्षेत्र के सौंदर्यीकरण में सुधार शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बनासकाँठा को 1004 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भेंट दी

गांधीनगर, 11 दिसंबर :बनासकाँठा जिले में शुक्रवार को विकास का महापर्व मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास कर जिलावासियों को भव्य भेंट दी।

श्री पटेल ने बनासकाँठा के 7 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 15 से अधिक बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करने के साथ वाव-थराद-बनासकाँठा जिले में नोबेल प्राइज एग्जीबिशन का भी उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी बच्चों में विज्ञान एवं प्रतियोगी परीक्षा के प्रति उत्साह जागृत करेगी। मुख्यमंत्री ने रामलीला मैदान से 'सशक्त नारी मेला' का प्रारंभ किया और स्वयं-सहायता समूहों की बहनों के साथ संवाद भी किया। शुक्रवार से शुरू हुए ये राज्यव्यापी स्वदेशी मेले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन' अभियान को और गति देंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास की राजनीति से सर्वांगीण विकास किया है। उनकी विजनरी लीडरशिप का जो लाभ ढाई दशक से राज्य को मिला है, उसमें अनेक मील के पत्थर पार हुए हैं। उनके दिशादर्शन में गुजरात दिन-प्रतिदिन तेजी से प्रगति कर रहा है।

श्री पटेल ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क

गुजरात में बन रहा है। एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड सिटी धोलेरा में डेवलप हो रही है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 'सूरत-चेन्नई एक्सप्रेसवे' गुजरात से शुरू होता है। भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र गिफ्ट सिटी-गुजरात में है। देश की प्रथम बुलेट ट्रेन भी गुजरात से शुरू होगी।

उन्होंने कहा कि मोदी साहब के नेतृत्व के चलते कल ही संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने दीपावली के पर्व को अमूर्त धरोहर के रूप में घोषित किया है, तो इससे पहले हमारा गरबा भी यह गौरव प्राप्त कर चुका है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के नौ संकल्पों के माध्यम से हम राष्ट्रप्रेम तथा देश के लिए कुछ करने की भावना जागृत करें। 'कैच द रेन', 'एक पेड़ माँ के नाम', 'स्वच्छता' जैसे अभियानों को हम अपनी आदत बनाएँ। प्राकृतिक खेती तथा गाय आधारित खेती अपनाएँ और स्वस्थ जीवनशैली के लिए योग एवं खेल-कूद को जीवन का हिस्सा बनाएँ।

उन्होंने स्वदेशी मेलों के गुजरात को आत्मनिर्भर बनाने तथा स्वदेशी को प्रोत्साहन देने के प्रेरक बल बनने की भूमिका देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत@2047 का लक्ष्य रखा है, जिसमें गुजरात भी आत्मनिर्भर एवं विकसित गुजरात से योगदान देने के लिए सज्ज है।

इस अवसर पर विधानसभा के अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी ने कहा कि वर्षों की समस्या का निवारण आया है। बनासकाँठा को बहुत बड़ी भेंट मिली है। उन्होंने इस भेंट के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का आभार व्यक्त किया। श्री चौधरी ने कहा कि सूखे-वीरान बनासकाँठा में नर्मदा की नहर लाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बनासकाँठा को हरियाला बनाते हुए विकास की शुरूआत की थी, जिसे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आगे बढ़ाते हुए करोड़ों रुपए की लागत से पाइपलाइनें डालकर बनासकाँठा के तालाब भरने का कार्य किया है। जिले को पानी की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने का राज्य सरकार ने दृढ़ आयोजन किया है।

कार्यक्रम में केबिनेट मंत्री श्री कुँवरजीभाई बावळिया, बनासकाँठा जिला प्रभारी मंत्री श्री कमलेशभाई पटेल, मंत्री श्री प्रवीणभाई माळी, मंत्री श्री संजयसिंह महिडा, मंत्री श्री स्वरूपजी ठाकोर, विधायक श्री अनिकेत ठाकर, विधायक श्री लविंगजी ठाकोर, जिला कलेक्टर श्री मिहिर पटेल, जिला विकास अधिकारी श्री एम. जे. दवे, जिला पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत सुंबे सहित अधिकारी तथा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

विकासखंड तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर में मनरेगा का बड़ा फजीर्वाड़ा उजागर

मजदूरों के हक पर डाका — ऑनलाइन अटेंडेंस में संख्या बड़ी, जमीन पर नदारद मजदूर

(जीएनएस)। बलरामपुर

विकासखंड तुलसीपुर से मिली सूत्रों की विश्वसनीय जानकारी के अनुसार मनरेगा योजनाओं में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। जितनी ऑनलाइन अटेंडेंस दिखाई जाती है, उतने मजदूर मौके पर काम करते नहीं मिलते। मीडिया की टीम जब विभिन्न कार्यस्थलों पर पहुंची तो कहीं कुछ मजदूर मिले, तो कहीं एक भी श्रमिक मौजूद नहीं था। यह स्थिति न केवल सरकारी धन की खुली लूट को दशार्ती है, बल्कि गरीब मजदूरों के हक पर सीधे डाका डालने जैसा है।

ग्राम पंचायत महादेया में मास्टर रोल पर 57 मजदूरों की ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज है, लेकिन मौके पर मात्र 12 मजदूर ही काम करते मिले। बाकी मजदूरों का रिकॉर्ड केवल कागजों और ऑनलाइन सिस्टम तक ही सीमित मिला।

ग्राम पंचायत गोपालपुर में स्थिति और भी चौंकाने वाली रही। यहां मास्टर रोल में 78 मजदूरों

की उपस्थिति दिखाई गई थी, जबकि वास्तविकता में सिर्फ 20 मजदूर कार्यस्थल पर मौजूद पाए गए। यह सीधे तौर पर अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत की ओर इशारा करता है।

ग्राम पंचायत सुगा नगर में फजीर्वाड़ा चरम पर मिला। दो मास्टर रोल में 30 मजदूरों की ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज थी, लेकिन जांच टीम को मौके पर एक भी मजदूर नहीं मिला। यह मनरेगा धन के दुरुपयोग का सबसे बड़ा प्रमाण बनकर सामने आया।

ग्राम पंचायत महादेव हरिहर नगर में चार मास्टर रोल पर 32 मजदूरों की ऑनलाइन अटेंडेंस दिखाई गई है, परंतु वास्तविक संख्या कितनी है, यह भी जांच के घेरे में है।

इन खुलासों ने विकासखंड तुलसीपुर में मनरेगा कार्यों की सच्चाई को सामने ला दिया है। यह स्पष्ट है कि कागजों और ऑनलाइन सिस्टम में मजदूरों की संख्या बढ़ाकर सरकारी पैसा निकाला जा रहा है, जबकि मजदूरों को उनका वास्तविक हक नहीं मिल पा रहा। संबंधित विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, जिनकी निगरानी की कमी से यह फजीर्वाड़ा फल-फूल रहा है।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि गरीब मजदूरों को उनका सही हक मिल सके और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बहाल हो सके।

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा आमजन की समस्याओं/शिकायतों की जनसुनवाई

त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

(जीएनएस)। बलरामपुर

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बलरामपुर में जनसुनवाई के दौरान जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए शिकायतकताओं/आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा प्रत्येक प्रकरण पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

प्रत्येक मामले में संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि वे समयबद्ध, प्रभावी एवं विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

राजस्व संबंधी मामलों में त्वरित समाधान हेतु पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें गठित कर, संबंधित स्थलों का निरीक्षण कर, गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र निस्तारण के निर्देश प्रदान किए गए।

यह जनसुनवाई कार्यक्रम आम जन की समस्याओं के निराकरण में पुलिस प्रशासन की संवेदनशीलता एवं तत्परता का परिचायक है।

नगर निकायों में जनसुविधाओं के उन्नयन के लेकर डीएम की अध्यक्षता में बैठक संपन्न, मा० चेयरमैनगण रहें उपस्थित

बैठक में नगर निकायों को स्वच्छ एवं सुंदर किए जाने हेतु वॉल पेंटिंग , रोप लाइट के साथ साथ बनाए वेंडिंग जोन

नगर पालिकाए एवं नगर पंचायतें हो अतिक्रमणमुक्त - डीएम

(जीएनएस)। बलरामपुर

कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में नगर निकायों की जनसुविधाओं एवं सुंदरीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा एवं आगे की कार्ययोजना को लेकर विस्तृत बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के मा० चेयरमैनगण, अधिशासी अधिकारियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, सौंदर्यीकरण व यातायात व्यवस्था को

बेहतर बनाना प्राथमिकता है। इस क्रम में सभी नगर निकायों में मुख्य मार्गों, चौराहों एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर आकर्षक वॉल पेंटिंग, थीम-आधारित रोप लाइट, लैंडस्केपिंग किए जाएँ। उन्होंने कहा कि यह कार्य न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाएंगे बल्कि जनजागरूकता को भी बढ़ावा देंगे।

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि प्रत्येक नगर निकाय में वेंडिंग जोन चिह्नित कर विकसित किए जाएँ। उन्होंने कहा कि वेंडिंग जोन से सड़क किनारे अनियमित रूप से लगने वाली दुकानों पर रोक लगेगी और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु रहेगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी नगर पालिकाएँ एवं नगर पंचायतें अपने क्षेत्र को पूरी तरह अतिक्रमणमुक्त रखें। इसके लिए नियमित अभियान चलाया जाए, साथ ही ऐसे स्थानों को चिन्हित कर स्थायी समाधान की दिशा में कार्य किया जाए जहाँ बार-बार अतिक्रमण होता है।

बैठक में नगर निकायों के चेयरमैनगण द्वारा विभिन्न स्थानीय समस्याएँ एवं सुझाव भी प्रस्तुत किए गए, जिन पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि नगर निकायों के विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा सभी योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण किया जाए।

बैठक में मा० चेयरमैन नगर पालिका बलरामपुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, चेयरमैन नगर पालिका उतरौला, चेयरमैन नगर पंचायत पचपेड़वा, गैंसडी , चेयरमैन प्रतिनिधि तुलसीपुर , एडीएम वित्त एवं राजस्व ज्योति राय , समस्त अधिशाषी अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी / कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

हर जरूरतमंद को शीतलहर से बचाने को सरकार प्रतिबद्धः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री ने रेलवे स्टेशन के पास और झूलेलाल मंदिर के पास बने रैन बसेरों का जायजा लिया.

गोरखपुरः (जीएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद को शीतलहर से बचाने और सुरक्षित आश्रय देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी रैन बसेरों को पूरी क्षमता से संचालित किया जा रहा है, जबकि तहसीलों और नगर निकायों को ऊनी वस्त्र, कंबल वितरण और अलाव की व्यवस्था के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करा दी गई है.

बुधवार देर शाम/रात मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर महानगर में दो रैन बसेरों का निरीक्षण किया और वहां ठहरे लोगों से बातचीत की. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर जरूरतमंद को रैन बसेरों में अच्छी व्यवस्था मिले. उन्होंने कहा कि सभी रैन बसेरों में पर्याप्त बिस्तर और कंबल होने चाहिए, साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए और जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है उन्हें भोजन भी उपलब्ध कराया जाए.

मुख्यमंत्री ने रेलवे स्टेशन के पास और झूलेलाल मंदिर के पास बने रैन बसेरों का जायजा लिया. उन्होंने रैन बसेरों में ठहरे जरूरतमंदों को अपने हाथों से कंबल और भोजन वितरित किया. रेलवे स्टेशन के पास रैन बसेरे के बाहर भी उन्होंने सैकड़ों लोगों को कंबल और भोजन देकर आश्वस्त किया कि सरकार उनकी सेवा को समर्पित है.

निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गगहा, चौरीचौरा के साथ बिहार से आए लोगों से भी बातचीत की. कई लोग परीक्षा, इलाज, रोजगार या अन्य कामों के सिलसिले में गोरखपुर आए थे. मुख्यमंत्री ने उनसे सुविधाओं के बारे में पूछा, जिस पर लोगों ने व्यवस्था को संतोषजनक बताया. सीएम से सीधे संवाद के दौरान कई लोग भावुक भी हो गए.

रैन बसेरों के निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि भीषण शीतलहर से बचाव के लिए शासन और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति फुटपाथ, प्लेटफॉर्म या सड़क पर खुले में न लेटने पाए. यदि कोई मिलता है, तो उसे तुरंत रैन बसेरे में पहुंचाया जाए और इसकी नियमित निगरानी की जाए.

सीएम ने बताया कि रैन बसेरों के संचालन को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा नगर निकायों और तहसीलों को जरूरतमंदों के लिए ऊनी वस्त्र और कंबल वितरण हेतु धन उपलब्ध करा दिया गया है. जहां भी आवश्यकता हो, अलाव की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है. उन्होंने कहा कि गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में 14 रैन बसेरे संचालित हो रहे हैं, जहां 700 से 1000 लोग आश्रय पा सकते हैं.

निरीक्षण के दौरान महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, कालीबाड़ी के महंत रवींद्रदास, नगर निगम बोर्ड के उपसभापति पवन त्रिपाठी, पार्षद ऋषिमोहन वर्मा, धर्मदेव चौहान सहित प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौजूद

विश्व मानव अधिकार दिवस पर जागरूकता कैंप का आयोजन

(जीएनएस)। रेवाड़ी

रेवाड़ी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निदेर्शानुसार एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी अमित वर्मा के आदेश अनुसार विश्व मानव अधिकार दिवस पर पैरा लीगल वॉलिंटियर संगीता यादव द्वारा बाल भवन रेवाड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकताओं के लिए एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया।

इस कैंप में पैरा लीगल वॉलिंटियर संगीता यादव ने बताया की दुनिया में हर व्यक्ति के जन्मसिद्ध अधिकारों की अहमियत को उजागर करने के लिए हर वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस सभी के लिए समानता स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र इन अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पैरा लीगल वॉलिंटियर संगीता यादव ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आमजन के लिए चलाए गए टोल फ्री नंबर 15100 एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 01274-220 062 चलाया हुआ है जिस पर आम जन किसी भी प्रकार के कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सिविल अस्पताल रेवाड़ी में ऑपरेशन के बाद छुट्टी मिलने के एक दिन बाद नवजात की तबीयत गंभीर, परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए

(जीएनएस)। रेवाड़ी। बुधवार को रेवाड़ी के सिविल अस्पताल में उस समय हंगामा मच गया जब एक नवजात शिशु की हालत अचानक बिगड़ने पर परिजन जोर-जोर से रोते-बिलखते नजर आए। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं।

परिजनों के अनुसार 6 तारीख को ऑपरेशन से डिलीवरी करवाई गई थी। मंगलवार को डॉक्टरों ने बच्चे को स्वस्थ बताकर छुट्टी दे दी थी। परिजनों का कहना है कि घर पहुंचने के कुछ ही समय बाद नवजात की तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद वे बुधवार सुबह दोबारा अस्पताल पहुंचे।

अस्पताल पहुंचने पर ड्यूटी डॉक्टरों ने नवजात की स्थिति गंभीर बताते हुए उसे रोहतक पीजीआईएमएस रेफर कर दिया।

इसी बात को लेकर परिजनों का कहना है:

'अगर बच्चा स्वस्थ नहीं था तो छुट्टी क्यों दी गई?

'डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हमारे बच्चे की हालत खराब हुई है।

घटना के बाद नवजात के दादी और पिता अस्पताल के बाहर बिलखते और रोते नजर आए। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन परिजन अस्पताल प्रशासन से बेहद नाराज दिखाई दिए।

पीएचसी रेहरा बाजार का सीएमओ ने किया निरीक्षण

तीन कर्मी पाए गए अनुपस्थित, वेतन रोकने के दिए आदेश

(जीएनएस)। बलरामपुर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने गुरुवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेहरा बाजार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने व्यवस्थाओं में कई खामियां पाईं।

निरीक्षण में तीन कर्मी अनुपस्थित पाए गए, जिनमें लैब टेक्नीशियन सूरज प्रताप सिंह, चिकित्सा अधिकारी डॉ. मोहम्मद रहमान और अशोक कुमार (चपरासी) शामिल रहे। लापरवाही पर कठोर रूख अपनाते हुए सीएमओ ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय भान को निर्देशित किया कि अनुपस्थित सभी कर्मियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोका जाए।

इसके अलावा, सीएमओ ने चिकित्सालय भवन एवं परिसर में साफझसफाई की कमी पर नाराजगी व्यक्त की और व्यवस्थाओं को सुधारने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रोगियों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना प्राथमिकता है, जिसके लिए अनुशासन एवं स्वच्छता दोनों अनिवार्य हैं।

सीएमओ ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी यदि ऐसी लापरवाही पाई गई तो संबंधित कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

72 घंटे तक पहचान न होने पर गोकल गेट पुलिस ने मानव अधिकार परिषद के सहयोग से किया लावारिस शव का अंतिम संस्कार

(जीएनएस)। रेवाड़ी। दिनांक 09 दिसंबर 2025 को गोकल गेट चौकी पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र में एक व्यक्ति का लावारिस शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि मृतक की उम्र लगभग 40 वर्ष प्रतीत हो रही थी। किसी प्रकार की पहचान न मिलने पर पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और पहचान के लिए इसे रेवाड़ी के सरकारी अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया।

चौकी पुलिस ने शव की पहचान के लिए लगातार प्रयास किए। आसपास के इलाकों में सूचना भेजी गई, थानों में जानकारी साझा की गई और लोगों से अपील भी की गई कि यदि कोई अपने परिजन को ढूंढ रहा है तो अस्पताल में रखे शव की पहचान करें।

लेकिन 11 दिसंबर 2025 तक, यानी 72 घंटों से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद शव की पहचान नहीं हो पाई। नियमों के अनुसार, इतने समय तक शव की पहचान न होने पर लावारिस शव का विधिवत अंतिम संस्कार किया जाना अनिवार्य होता है।

इसी के तहत गोकल गेट चौकी पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए मानव अधिकार परिषद के संगठन मंत्री विनोद सक्सेना के सहयोग से इस लावारिस शव का अंतिम संस्कार कराया। यह अंतिम संस्कार विधि-विधान के साथ किया गया ताकि मृतक को सम्मानपूर्वक विदाई दी जा सके।

इस नेक कार्य में सिपाही सुनील कुमार, सिपाही अशोक कुमार सहित मानव अधिकार परिषद की टीम मौजूद रही। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस और मानव अधिकार परिषद के इस मानवीय कदम की सराहना की है।

बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

(जीएनएस)। रेवाड़ी। जिला को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत जिला के आंगनबाड़ी, स्कूल और कॉलेज सहित 100 गांवों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डीसी अभिषेक मीणा के मार्गदर्शन में गुरुवार को बाल विवाह निषेध विभाग द्वारा बावल के सूरज स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कड़ी में डीसी अभिषेक मीणा के मार्गदर्शन में गुरुवार को बाल विवाह निषेध विभाग द्वारा बावल के सूरज स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ भी दिलवाई गई।

बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय के प्रमोद कुमार ने बाल विवाह के खतरे, संबंधित कानूनों और रोकथाम के उपायों पर जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत लडकी की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लडके की 21 वर्ष होनी आवश्यक है। इससे कम उम्र में शादी कराना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 2 वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपये तक जुमार्ना का प्रावधान है। झूठी शिकायत करने पर भी कार्रवाई होगी। बाल विवाह की सूचना 112, 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), निकटतम पुलिस थाने, आंगनवाड़ी वर्कर या संबंधित अधिकारियों को दी जा सकती है।

उन्होंने सभी स्कूल प्राचार्य से आह्वान किया कि वे 15 दिसंबर तक अपने-अपने स्कूल में बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ दिलवाएं।

'नशा मुक्त रेवाड़ी' अभियान के तहत पुलिस ने तीन सरकारी स्कूलों में छात्रों को किया जागरूक

नशा छोड़ो, जिंदगी से नाता जोड़ोह्व संदेश के साथ युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया

(जीएनएस)। रेवाड़ी। पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी श्री हेमेंद्र कुमार मीणा, आईपीएस के निर्देशन में जिले में 'नशा मुक्त रेवाड़ीह्व अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर जागरूकता गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में निरीक्षक रामपाल के नेतृत्व में गठित नशा मुक्ति टीम ने गुरुवार को गवर्नमेंट स्कूल गोठड़ा टप्पा डहीना, सिहा और लिसान में छात्रों को नशे के खतरों के प्रति जागरूक किया।

टीम के सदस्यों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज—तीनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाता है बल्कि युवाओं का भविष्य भी अंधकारमय कर देता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे पढ़ाई, खेल और अपने सपनों पर ध्यान दें तथा नशे जैसी बुरी लत से दूर रहें।

नशा मुक्ति टीम ने कहा कि — 'नशा केवल शरीर ही नहीं, जीवन और समाज के लिए भी जहर है। आज के विद्यार्थी ही कल का भविष्य हैं, इसलिए स्वस्थ रहना ही देश की प्रगति की गारंटी है।

टीम ने सभी छात्रों से 'नशा मुक्त रेवाड़ी' मिशन में योगदान देने की अपील की।

सायबर अपराध से भी कराया जागरूक

टीम ने विद्यार्थियों को बताया कि आजकल साइबर ठग फोन कॉल, सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डळढ, पासवर्ड और अन्य निजी जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं।

उन्होंने छात्रों को आगाह किया कि किसी भी अनजान व्यक्ति से अपनी निजी जानकारी बिल्कुल साझा न करें।

यातायात नियमों की दी जानकारी

इस दौरान टीम ने ट्रैफिक नियमों की भी जानकारी दी। विद्यार्थियों को हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात संकेतों का पालन करने की सलाह दी गई ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने की अपील

निरीक्षक रामपाल ने कहा कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन, असामाजिक गतिविधि या नशे से संबंधित सूचना तुरंत पुलिस को दें।

उन्होंने बताया कि: आपात स्थिति में डायल 112 नशा संबंधित सूचना के लिए टअठअर हेल्पलाइनः 1933 पर जानकारी दें। उन्होंने आश्वासन दिया कि सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

छात्रों ने ली नशा मुक्ति की शपथ

इस जागरूकता कार्यक्रम का विद्यार्थियों ने स्वागत किया और नशा तथा साइबर अपराधों से दूर रहने का संकल्प लिया।

सभी ने मिलकर नशा मुक्त रेवाड़ी बनाने की प्रतिज्ञा दोहराई।

सभी कार्यालयों में कार्यस्थल पर शुरू हुआ पांच मिनट का योगा ब्रेक (वाई-ब्रेक)

वाई-ब्रेक से तनाव मुक्त होकर एकाग्रता के साथ कार्य करने की बढ़ेगी क्षमता:डीसी

(जीएनएस)। रेवाड़ी। आयुष विभाग द्वारा कार्यस्थल पर माहौल को अनुकूल बनाने और अधिकारियों-कर्मचारियों को तनाव मुक्त रह कर कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 'वाई-ब्रेक' देने का निर्णय लिया गया है। वाई-ब्रेक यानी योग के लिए ब्रेक कार्यदिवस में पांच मिनट के लिए होगा।

डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा अधिकारियों-कर्मचारियों को अब कार्यस्थल पर प्रत्येक कार्यदिवस पर कुछ ऐसी क्रियाएं और सरल योग के आसन करने के लिए समय दिया गया है, जिससे वह तनाव से मुक्त होकर और बेहतर तरीके से काम कर सकें। वाई-ब्रेक पांच मिनट का होगा। वाई-ब्रेक में शरीर को राहत के लिए आंखों, कंधों, कमर और अन्य अंगों के लिए क्रियाएं कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर माहौल को अनुकूल बनाने और अधिकारियों-कर्मचारियों को तनावमुक्त रह कर कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करना है।

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा योग आयोग की ओर से जिला सचिवालय सहित सभी कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन 5 मिनट का 'वाई-ब्रेक' सत्र का आयोजन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस लघु योगाभ्यास की अनुशंसा आयुष मंत्रालय द्वारा की गई है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, एकाग्रता बढ़ाने और काम के दौरान तनाव व थकान को कम करने में मदद मिलेगी। है। वाई-ब्रेक के लिए हरियाणा योग आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक https://yoga.ayush.gov.in/pm-gallery-other/y-break और अन्य वीडियो व सामग्री का उपयोग किया जा सकता है।

डीसी ने बताया कि विशेषज्ञों के अनुसार यह 5 मिनट का योग ब्रेक लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से होने वाली तकलीफों को कम करने, रक्त संचार को बेहतर करने तथा मानसिक एकाग्रता बढ़ाने में अत्यंत सहायक है। यह पहल केंद्र सरकार द्वारा तैयार वाई-ब्रेक योग प्रोटोकॉल पर आधारित है, जिसका उद्देश्य व्यस्त कार्यस्थलों पर भी योग को सरल और व्यावहारिक रूप से अपनाने को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि कार्यकुशलता, सकारात्मकता और टीम भावना को भी मजबूत करता है।

जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ बसंत कुमार ने जिला के सभी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रतिदिन योग सत्र में भाग लेने का आह्वान किया।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सुधार और आधुनिकीकरण

पिछले एक वर्ष में उत्खनन शाखाओं में तैनात कर्मचारियों की संख्या 86 से बढ़कर 102 हो गई है

प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के अध्ययन और प्रलेखन के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है

(जीएनएस)। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की उत्खनन शाखाओं में कर्मचारियों की भर्ती, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से भर्ती और योग्य अधिकारियों की पदोन्नति सहित भर्ती नियमों के अनुसार स्वीकृत पदों को नियमित रूप से भरकर की जाती है। पिछले एक वर्ष में उत्खनन शाखाओं में तैनात कर्मचारियों की संख्या 86 से बढ़कर 102 हो गई है। इसके अलावा, चलाई जा रही उत्खनन परियोजनाओं की परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर उपलब्ध मानव संसाधन का तर्कसंगत उपयोग किया जाता है। समय-समय पर आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से फील्ड स्टाफ की क्षमता निर्माण किया जाता है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चालू वित्त वर्ष में दिसंबर 2025 तक उत्खनन/अन्वेषण के लिए 24 अनुमतियां जारी की गई हैं। तकनीकी रिपोर्ट तैयार करना प्रत्येक उत्खनन का अभिन्न अंग है, इसे उत्खनन पूर्ण होने के बाद प्रस्तुत करना अनिवार्य है। शैक्षणिक और पुरातात्विक सहयोग की प्रकृति अलग-अलग होती है, इनकी अवधि की कार्यान्वयन के लिए सम्बंधित विभागों द्वारा विधिवत रूप से जांच की जाती है।

लिडार, जीआईएस, ड्रोन आदि जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के अध्ययन और प्रलेखन के लिए किया जा रहा है, इसमें मानचित्रण भी शामिल है। इन तकनीकों का उपयोग संसाधनों की आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार किया जा रहा है। प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 और नियम 1959 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी अधिकार है। अतिक्रमणों को नियंत्रित करने और हटाने में समय-समय पर सम्बंधित राज्य सरकार/पुलिस अधिकारियों से भी सहायता ली जाती है।

पुरातत्वविद् को सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करना) अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली नोटिस/आदेश जारी करने के लिए संपदा अधिकारी के समान अधिकार दिए गए हैं। उन्हें प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 और नियम 1959 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी अधिकार है। अतिक्रमणों को नियंत्रित करने और हटाने में समय-समय पर सम्बंधित राज्य सरकार/पुलिस अधिकारियों से भी सहायता ली जाती है।